धर्म–अर्थ सम्बन्ध : मिथ्या एवं वास्तविकता

–मुकेश कुमार पाण्डेय* एवं डॉ० अमित भूषण**
*असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
का० सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
**असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर, मध्य प्रदेश।

सार (Abstract)

धर्म एवं अर्थव्यवस्था का आपसी सम्बम्ध जितना प्राचीन रहा है उतना ही गहरा भी रहा है। भारतीय धर्मों में उपासना एवं पूजा–अर्चना के लिए मन्दिरों को अतिविशिष्ट स्थान प्राप्त है। भारत में जिन स्थानों पर महत्वपूर्ण दर्जे के मन्दिरों का निर्माण हुआ है, वहाँ स्वयं ही एक बाज़ार अर्थव्यवस्था विकसित हो गई है। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारम्भ सिर्फ़ आस्था और धर्म का प्रतिबिम्ब नहीं है, अपितु इस बात का भी प्रतीक है कि मन्दिरों के अर्थशास्त्र का देश के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना काल में देश के मन्दिरों ने सरकारी ख़ज़ाने में राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी मन्दिरों का अभूतपूर्व योगदान है। इसलिए नीति बनाते समय धर्म, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अंर्तसम्बन्धों को समेकित रूप में समझने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द (Key Words): धर्म, अर्थव्यवस्था।

धर्म–अर्थ सम्बन्ध : मिथ्या एवं वास्तविकता

उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में निहित अन्तर्विरोधों के साए में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में अमूल्य योगदान देने वाले धार्मिक संस्थाओं पर अनावश्यक एवं झूठा प्रहार वर्तमान समय में अधिक मुखर हो चला है। नए परिवेश में, अनियन्त्रित सामाजिक मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों ने इसे और अधिक विकृत किया है। प्रायः ऐसा वर्णन निर्मित होता है, जिसमें मन्दिरों को अर्थव्यवस्था एवं जन–जीवन के व्यवहारिक पक्षों के विरुद्ध दर्शाया जाता है। ऐसे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि देश में शिक्षा व्यवस्था एवं अस्पतालों की बदहाली के लिए मन्दिरों का निर्माण एवं रखरखाव ही उत्तरदायी है। इस प्रकार के कुतर्क एक सोची–समझी रणनीति का ही हिस्सा हो सकते हैं। जब धर्म को व्यक्तिगत एवं पारलौकिक अवधारणा तक सीमित कर इसे व्यक्ति समाज एवं देश के विरुद्ध खड़ा करने की चेष्टा की जाती है, तो धर्म–अर्थ सम्बन्धों के विविध आयामों का विश्लेषण अपरिहार्य हो जाता है । धर्म–अर्थ सम्बन्धों पर अध्ययन न केवल धर्म की स्थापना हेतु आवश्यक है, बल्कि समाज एवं देश के कल्याण हेतु भी इसका नीतिगत महत्व है। भारत में धर्म एवं अर्थ के बीच तथा मन्दिरों के अर्थशास्त्र पर सीमित मात्रा में परन्तु महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। विशेषकर, भारतीय धर्म संस्कृति में रुचि रखने वाले बहुत से विदेशी विद्वानों ने भी इस हेतु अध्ययन की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः प्रस्तुत आलेख भारत में मन्दिरों के सामाजिक–आर्थिक योगदान पर केन्द्रित है।

धर्म की उपादेयता :

धर्म का सम्बन्ध धार्मिक उपासना, पूजा –अर्चना, नीति, मूल्यों तक ही सीमित नहीं है। धर्म, व्यापक अर्थों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उपक्रमों का प्रतिबिम्ब होता है। यह किसी समाज, देश को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। भारतीय धर्मों में (सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म आदि) उपासना एवं पूजा अर्चना के लिए मन्दिरों को अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। गुप्त काल (चौथी से छठी शताब्दी) से ही मन्दिरों के निर्माण का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है।

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मन्दिर बहुआयामी क्रियाकलापों के केन्द्र रहे हैं। मन्दिरों के खुले प्रांगण में सामाजिक कार्यक्रमों, भजन–कीर्तन, निराश्रितों हेतु अस्थाई प्रवास, भोजन–व्यवस्था आदि की समृद्ध परम्परा रही है। इसके अलावा मन्दिरों में तर्क–वितर्क की परम्परा भारतीय लोकतान्त्रिक परम्परा को और भी सुदृढ़ करते हैं।

धर्म और अर्थव्यवस्था :

धर्म एवं अर्थव्यवस्था का आपसी सम्बन्ध जितना प्राचीन रहा है उतना ही गहरा भी रहा है। किन्तु आगे चलकर दोनों के आपसी सम्बन्ध बहुत विवादास्पद भी रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सदियों तक बाज़ार धर्म द्वारा निर्देशित होता रहा है। लगभग सभी धर्मों की प्राचीन ग्रन्थों में हमें आर्थिक विचार प्राप्त होते हैं। किन्तु समय के साथ बाज़ार अर्थव्यवस्था पर धर्म का नियन्त्रण समाप्त होता गया और अर्थव्यवस्था पर राजसत्ता का नियन्त्रण एवं प्रभाव बढ़ता गया। यद्यपि कि आर्थिक गतिविधियों पर राज्य या सत्ता का नियन्त्रण स्थापित हो गया फिर भी धार्मिक स्थल व्यापार, वाणिज्य, देशाटन का प्रमुख केन्द्र बने रहे। वर्तमान समय में भी हम आसानी से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जहाँ–जहाँ पवित्र धार्मिक स्थल हैं वे आज भी पर्यटन, व्यापार, वाणिज्य के बड़े केन्द्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही समय के साथ धर्म–अर्थ का नियन्त्रणकारी सम्बन्ध विलोप हुआ है किन्तु आज भी पवित्र धार्मिक स्थल अनेक रूपों में आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बने हुए ळें

भारत में जिन स्थानों पर महत्वपूर्ण दर्जे के मन्दिरों का निर्माण हुआ है वहां स्वयं ही एक बाजार अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई है। भारत में मन्दिरों के द्वारा आर्थिक कार्य भी सम्पादित होते हैं (Burton 1960)। आय एवं रोजगार का सृजन, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष उत्पादन गतिविधियों का एक तन्त्र क्रियाशील हुआ है। इन मन्दिरों के माध्यम से सामाजिक सेवाओं की पूर्ति भी होती है (Iyer 2018)। मन्दिरों के अर्थ तन्त्र में मुख्यधारा की समष्टि अर्थव्यवस्था की तरह आय की विषमता, पूँजीवादी शोषण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक लक्षण भी विद्यमान पाये गये हैं। तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप इन स्थानों पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के निवेश भी आकर्षित होते हैं, जो सम्बन्धित क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। अयोध्या में मन्दिर का निर्माण एवं वाराणसी में काशी–विश्वनाथ कॉरिडोर का आरम्भ सुन्दर उदाहरण है।

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा काशी–विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारम्भ सिर्फ़ आस्था और धर्म का प्रतिबिम्ब नहीं है अपितु इस बात का भी प्रतीक है कि मन्दिरों के अर्थशास्त्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण स्थान है। एक अनुमान के अनुसार धार्मिक यात्राओं की देश के सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी 2.32% है, एवं मन्दिरों के देश के सकल घरेलू

उत्पादन में हिस्सेदारी तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यदि मन्दिरों की भागीदारी का मूल्यांकन रोजगार की दृष्टि से किया जाए तो यह ज्ञत होता है कि देश के असंगठित क्षेत्र का रोजगार जो कि कुल रोजगार का 90% है, उनमें मन्दिरों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गया रोजगार भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र में संलग्न व्यापारी जैसे होटल एवं रेस्टोरेंट के व्यवसाई शामिल हैं। भारत के बड़े एवं महत्वपूर्ण मन्दिर स्थलों पर बड़ी संख्या में होटल एवं अन्य जनउपयोगी सुविधाओं का निर्माण हुआ है जिनमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त है।

इसके अलावा, असंगठित श्रमिक जैसे रिक्शा चालक, टेंपो चालक, फल विक्रेता, फूल विक्रेता, प्रसाद विक्रेता, नारियल विक्रेता, फुटकर सामग्री विक्रेता, खिलौनों के विक्रेता आदि को रोजगार प्राप्त है। विदित है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले ये श्रमिक वंचित समुदाय से सम्बन्धित होते हैं, और बहुत ही कम मजदूरी दरों पर काम करने को विवश होते हैं। स्पष्ट है कि गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के दृष्टिकोण से भी मन्दिरों के योगदान की तिलांजलि नहीं दी जा सकती है। देश के बहुत से बड़े मन्दिरों के ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना काल में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में जहाँ निजी अस्पतालों ने अवैध धन उगाही के किसी भी उपाय को बेकार नहीं जाने दिया, वहीं देश के मन्दिरों ने सरकारी खज़ाने में राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है । इनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकार हैः–

1. कांची मठ, 10 लाख केन्द्रीय राहत कोष में एवं 10 लाख राज्य सरकार के राहत कोष में योगदान।
2. महावीर मन्दिर पटना, 1 करोड़ का केन्द्र सरकार के राहत कोष में योगदान।
3. माता वैष्णो देवी मन्दिर।
4. महामाया मन्दिर ट्रस्ट छत्तीसगढ़ द्वारा 5 लाख 11 हजार रुपए का राज्य सरकार के राहत कोष में योगदान।
5. श्री सोमनाथ मन्दिर, गुजरात के द्वारा 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 1 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के राहत कोष में योगदान।
6. अम्बाजी मन्दिर के द्वारा गुजरात सरकार के राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान।
7. श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार के राहत कोष में 51 करोड़ का योगदान।
8. देवस्थान प्रबन्धन समिति, कोल्हापुर के द्वारा राज्य सरकार के राहत कोष में दो करोड़ रुपए का योगदान।
9. स्वामीनारायण मन्दिर के द्वारा गुजरात सरकार के राहत कोष में 1.88 करोड़ रुपए का योगदान।

इसके अतिरिक्त, बाबा रामदेव ने प्रधानमन्त्री आपदा राहत कोष में 25 करोड़ का योगदान दिया है। ऐसे अनेकों धार्मिक संस्थान हैं जिन्होंने कोरोना काल में सरकार के राहत कोष में योगदान किया हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं है। इस योगदान के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान में भी मन्दिर अग्रणी भूमिका निभाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित छोटे मन्दिरों के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि इनके परिसरों में योग अभ्यास और व्यायाम

जैसे क्रिया–कलाप भी संचालित होते हैं। इन प्रांगणों में वृक्षारोपण और स्वच्छता के समुचित उपाय भी होते हैं। विनोद कुमार और अरुणा (2018) ने अपने अध्ययन में पाया है कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अति आवश्यक पौधा–वृक्षों के संरक्षण में मदुरै जिले के मन्दिरों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। हालाँकि, उत्तर भारत के मन्दिरों के लिए ये तथ्य उतना सत्य नहीं प्रतीत होता है।

कुछ वर्ष पूर्व, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अनुमान लगाया था कि भारत के पास लगभग 24000 टन सोने का भंडार है, जिसमें मन्दिरों के पास लगभग 3000–4000 टन संरक्षित है। बहुत से विशेषज्ञ इस सोने को देश के आर्थिक विकास में प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझावः

निष्कर्ष है कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन एवं पर्यावरण संरक्षण आदि के दृष्टिकोण से धार्मिक मन्दिरों का महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अर्न्तसम्बन्धों को समेकित रूप में समझने की आवश्यकता है। सरकार को योजना बनाते समय मन्दिरों के विकास एवं संरक्षण की नीति को भी शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान एवं धर्म विज्ञान के विद्वानों को भी इन अर्न्तसम्बन्धों के नए आयामों पर शोध करने की अनिवार्यता है। इनके सामाजिक–आर्थिक निहितार्थ हैं।

सन्दर्भ सूची :

1. Iyer, Sriya (2018): The Economics of Religion in India, Harvard University Press
2. Stein, Burton (1960): The Economic Function of a Mediaeval South Indian Temple, *The Journal of Asian Studies*, 19(2), pp 163-176.
3. Kumar A Vinoth, R Aruna(2018): A Study of Sthalavrikshas in Temples of Madurai District, Tamilnadu, *International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources* 13(3), 71-76.